भारतीय वैश्विक परिषद

समाचार पत्रक

अंक : 26 | जुलाई-सितंबर 2021

भारत के उपराष्ट्रपति और आईसीडब्ल्यूए के अध्यक्ष श्री वेंकैया नायडू ने राजदूत विजय ठाकुर सिंह को भारतीय वैश्विक परिषद (आईसीडब्ल्यूए) का नया महानिदेशक नियुक्त किया है।

मुख्य विशेषताएं

- परिषद की 20वीं शासी निकाय की बैठक और 19वीं शासी निकाय की बैठक हाइब्रिड मोड में हुई।
- समाज में सामान्य स्थिति हो रही हैं और परिषद ने पिछली तिमाही में वस्तुतः और हाइब्रिड मोड में वेबिनार आयोजित चुनिंदा दर्शको ने भाग लिया।
- 38वां सप्रू हाउस व्याख्यान मालदीव गणराज्य के विदेश मामलों के मंत्री महामहिम श्री अब्दुल्ला शाहिद ने दिया।
- महामहिम निकोला सेलाकोविच, सर्बिया के विदेश मामलों के मंत्री ने एक विशेष व्याख्यान दिया।
- विदेश मंत्रालय की सचिव (पूर्व) श्रीमती रिवा गांगुली दास ने "हिंद-प्रशांत महासागर पहल" पर राष्ट्रीय परामर्श में मुख्य भाषण दिया।
- इस तिमाही के दौरान परिषद ने दो आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन किया।
- आईसीडब्ल्यूए ने आईसीडब्ल्यूए वेबसाइट पर अनुसंधान संकाय द्वारा प्रकाशित 47 लेखों के साथ विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर नज़र बनाए रखी।
- इस अवधि में परिषद द्वारा छह पुस्तकें प्रकाशित की गई।

विषय-सूची

राजदूत विजय ठाकुर सिंह की भारतीय वैश्विक परिषद् के महानिदेशक के रूप में नियुक्ति हुई। 4

आईसीडब्ल्यूए- नेताजी इंस्टीट्यूट फॉर एशियन स्टडीज (एनआईएस), कोलकाता ने संयुक्त रूप से ऑनलाइन पुस्तक विमोचन किया और चार हालिया एनआईएस प्रकाशनों पर चर्चा की, 02 जुलाई 2021 4

आईसीडब्ल्यूए के शासी निकाय की 19वीं बैठक के पश्चात आईसीडब्ल्यूए की शासी परिषद की 20वीं बैठक हुई, 03 जुलाई 2021 5

डॉ. अमित दास गुप्ता, द्वारा 07 जुलाई 2021 को "द इंडियन सिविल सर्विस एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर ऑनलाइन पुस्तक चर्चा, 1923-1961" 6

महामहिम श्री अब्दुल्ला शाहिद, मालदीव गणराज्य के विदेश मामलों के मंत्री और 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्वाचित अध्यक्ष द्वारा 38वां सप्रू हाउस व्याख्यान, 23 जुलाई,2021 7

डॉ. टी.सी.ए राघवन का विदाई समारोह, 23 जुलाई 2021 7

आईसीडब्ल्यूए-सीपीपीआर का "रणनीतिक भविष्य: क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा परिसरों (पश्चिमी प्रशांत रिम; हिंद महासागर - दक्षिणी महासागर; और अरब सागर तटवर्ती पर एक दिवसीय आभासी सम्मेलन), 18 अगस्त 2021 8

"संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों की प्रभावशीलता: संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों पर सैनिकों और विविधता की संरचना की गतिशीलता" पर शांति स्थापना पर आईसीडब्ल्यूए-यूएसआई वेबिना की श्रृंखला में तृतीय, 25 अगस्त 2021 8

भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग" डॉ. टेम्जेनमरेन एओ द्वारा लिखित "दक्षिण पूर्व एशिया के लिए कनेक्टिविटी का निर्माण:, पर सप्रू हाउस पेपर (एसएचपी) पर चर्चा 31 अगस्त 2021 9

"भारत-प्रशांत एशियाई पहल (आईपीओआई) पर राष्ट्रीय परामर्श", 3 सितंबर 2021 9

यू.एल. बरुआ द्वारा रचित "एक बांग्लादेश युद्ध टीका", पर डॉ.. हसन महमूद, माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री, बांग्लादेश लोकतंत्र गणराज्य सरकार द्वारा पुस्तक विमोचन चर्चा, 07 सितंबर 2021 10

सप्रू हाउस पेपर (एसएचपी) पर चर्चा डॉ.. स्तुति बनर्जी द्वारा लिखित "चुप्पी तोड़ना: आर्कटिक में रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका" पर सप्रू हाउस पेपर चर्चा, 8 सितम्बर,2021 10

"ग्रैंड इथियोपिया के पुनर्जागरण बांध और जल बंटवारे की राजनीति- भारत से एक दृश्य" पर वेबिनार, 17 सितंबर 2021 11

महामहिम निकोला सेलाकोविच, सर्बिया के विदेश मामलों के मंत्री द्वारा भारत-सर्बिया संबंध: खेल और भविष्य की क्षमता के राज्य विषय पर विशेष व्याख्यान , 20 सितंबर 2021 11

"चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 वर्ष " पर वेबिनार, 28 सितंबर 2021 12

आउटरीच कार्यक्रम 13

इंडिया क्वार्टरली सम्पादकीय 15

प्रकाशन 16

राजदूत विजय ठाकुर सिंह की भारतीय वैश्विक परिषद के महानिदेशक के रूप में नियुक्ति जुलाई 2021

राजदूत विजय ठाकुर सिंह को भारत के उपराष्ट्रपति और आईसीडब्ल्यूए के अध्यक्ष श्री वेंकैया नायडू द्वारा भारतीय वैश्विक परिषद (आईसीडब्ल्यूए) का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। राजदूत सिंह ने 24 जुलाई, 2021 से पदभार ग्रहण किया।

राजदूत विजय ठाकुर सिंह ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। वह 1985 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुईं।

उनकी पहली तैनाती मैड्रिड, स्पेन में भारत के दूतावास में हुई थी, जहां बाद में वे 2006 में मिशन के उप प्रमुख के रूप में गईं। उन्होंने 1989 से 1999 तक विदेश मंत्रालय में रहकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों को संभाला। वे 2003 से 2005 तक काबुल में भारतीय दूतावास में काउंसलर के पद पर तैनात रहीं।

उनका बहुपक्षीय अनुभव है, विशेष रूप से आर्थिक और पर्यावरण के मुद्दों में। वे 2000 से 2003 तक न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में सलाहकार रहीं। वे अगस्त 2007 से अगस्त 2012 तक भारत के राष्ट्रपति की संयुक्त सचिव और 2012 से 2013 तक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य कर चुकी हैं।

वे 2013 से 2016 तक सिंगापुर में भारत की उच्चायुक्त और 2016 से 2018 तक आयरलैंड में भारत की राजदूत रही हैं।
वे 2018 से दो वर्ष तक वह विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) रहीं और सितंबर 2020 में सेवानिवृत्त हुईं।

आईसीडब्ल्यूए-नेताजी इंस्टीट्यूट फॉर एशियन स्टडीज (एनआईएस), कोलकाता द्वारा संयुक्त ऑनलाइन पुस्तक विमोचन और चार हालिया एनआईएस प्रकाशनों पर चर्चा, 02 जुलाई 2021

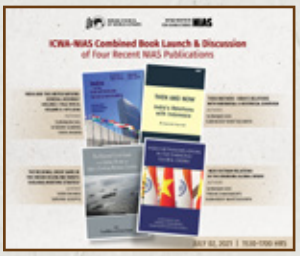

भारतीय वैश्विक परिषद ने नेताजी इंस्टीट्यूट फॉर एशियन स्टडीज (एनआईएस) के साथ साझेदारी में एनआईएस के चार हालिया प्रकाशनों : 1) भारत और संयुक्त राष्ट्र महासभा, खंड I: 1945-1970 और खंड II: 1971-2018 सुरंजन दास, सीताराम शर्मा और विवेक मिश्रा द्वारा, केडब्ल्यू प्रकाशक (2019) ; 2) तब और अब - इंडोनेशिया के साथ भारत के संबंध: ऐतिहासिक अवलोकन सुरंजन दास और सुभदीप भट्टाचार्य द्वारा, केडब्ल्यू प्रकाशक (2020) ; 3) हिंद महासागर में क्षेत्रीय महान खेल और भारत की उभरती समुद्री रणनीति, विवेक मिश्रा और सरवाणी गूप्टू द्वारा संपादित, केडब्ल्यू प्रकाशक (2020); और 4) उभरते वैश्विक क्रम में भारत-वियतनाम संबंध, सुरंजन दास, त्रिदिब चक्रवर्ती और सुभदीप भट्टाचार्य द्वारा (केडब्ल्यू पब्लिशर्स, नई दिल्ली: 2018) का संयुक्त पुस्तक विमोचन किया।

कार्यक्रम का शुभारंभ आईसीडब्ल्यूए के अध्येता डॉ. विवेक मिश्रा ने स्वागत भाषण और वक्ताओं का परिचय देते हुए किया। इसके बाद आईसीडब्ल्यूए के महानिदेशक डॉ. टी.सी.ए. राघवन ने एनआईएस ने चारों प्रकाशनों के महत्व पर जोर दिया। विशेष रूप से उन्होंने सुरंजन दास और सुभदीप भट्टाचार्य की पुस्तक की प्रशंसा की, जिसका शीर्षक था, तब और अब-इंडोनेशिया के साथ भारत के संबंध एक ऐतिहासिक अवलोकन। वर्चुअल कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो. सुरंजन दास ने की। उन्होंने एनआईएस के विजन और संस्थान द्वारा प्रकाशित चार प्रकाशनों के महत्व को रेखांकित किया। इसके बाद आईसीडब्ल्यूए के महानिदेशक डॉ. टी. ए. राघवन ने चार प्रकाशनों का संयुक्त विमोचन किया। अध्यक्षता प्रो. सुरंजन दास ने की। और पैनलिस्ट, राजदूत अशोक मुखर्जी; राजदूत सुधीर देवरे; प्रो. अमिताभ मट्टू; राजदूत राजीव भाटिया, सीताराम शर्मा और प्रो. सरवाणी गूट्टू थे। चारों प्रकाशनों के ऑनलाइन विमोचन के बाद प्रत्येक प्रतिभागी ने टिप्पणी की।

राजदूत अशोक मुखर्जी नेअपनी टिप्पणी में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की भागीदारी पर दो खंडों का विश्लेषण करने में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में अपने वर्षों के नुभव का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की भागीदारी पर अनुवर्ती मात्रा बहुत जरूरी है। इंडोनेशिया के साथ भारत के संबंध एक ऐतिहासिक अवलोकन, नामक पुस्तक पर अपनी टिप्पणी में सुधीर टी देवरे ने कहा कि इस पुस्तक ने इंडोनेशिया के इतिहास को अपने वर्तमान से व्यापक रूप से जोड़ा है और विशेष रूप से युवा विद्वानों के लिए पढ़ा जाना चाहिए। राजदूत राजीव भाटिया ने हिंद महासागर में क्षेत्रीय महान खेल और भारत की विकसित समुद्री रणनीति शीर्षक से संपादित खंड पर टिप्पणी करते हुए कहा कि काम चिकित्सकों के साथ-साथ शिक्षाविदों को समान रूप से तैयार करता है और इसलिए हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका पर संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। उन्होंने यह भी बताया कि 2017 में सम्मेलन से लंबी अवधि, जिसमें इस खंड का प्रकाशन हुआ।
प्रो. अमिताभ मट्टू ने उभरते वैश्विक क्रम में भारत-वियतनाम संबंधों की पुस्तक का विश्लेषण किया और अन्य देशों खासकर चीन और अमेरिका के साथ वियतनाम के संबंधों के बदलते स्वरूप को रेखांकित किया। अपने समापन भाषण में सीताराम शर्मा और प्रोफेसर सरवाणी गूट्टू ने उन दो प्रकाशनों में अपने-अपने योगदान के बारे में बताया, जिनमें से वे एक हिस्सा हैं, नामत यूएनजीए में भारत की भूमिका और हिंद महासागर के ऐतिहासिक कनेक्शन।

आईसीडब्ल्यूए के शासी निकाय की 19वीं बैठक के बाद आईसीडब्ल्यूए की शासी परिषद की 20वीं बैठक, 03 जुलाई 2021

डॉ. अमित दास गुप्ता द्वारा "द इंडियन सिविल सर्विस एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी", पर ऑनलाइन पुस्तक चर्चा 1923-1961, 07 जुलाई 2021

आईसीडब्ल्यूए ने 07 जुलाई 2021 को डॉ. अमित दास गुप्ता द्वारा भारतीय सिविल सेवा और भारतीय विदेश नीति, 1923-1961 पर एक ऑनलाइन पुस्तक चर्चा आयोजित की। पुस्तक परिचर्चा की अध्यक्षता भारत के पूर्व विदेश सचिव राजदूत निरूपमा मेनन राव ने की। पैनलिस्टों में शामिल थे: यूनीवर्सिट डेर बुंदेवेर, म्यूनचेन, जर्मनी के वरिष्ठ शोधकर्ता चर्चा की जा रही पुस्तक के लेखक, डॉ. अमित दास गुप्ता; डॉ. अनुपम रे, संयुक्त सचिव, पीपीएंडआर डिवीजन, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, प्रो माधवन के. पलावत, इतिहासकार और संपादक, नेहरू के चयनित कार्य; डॉ. रुद्र चौधरी, निदेशक, कार्नेगी इंडिया; और डॉ. जोरावरदौलेट सिंह, लेखक और विदेश मामलों के विश्लेषक।

राजदूत निरूपमा राव ने नई पुस्तक पर लेखक को बधाई देते हुए अपनी टिप्पणी शुरू की और कहा कि पुस्तक के माध्यम से कोई भी भारत की विदेश नीति का यह अभिज्ञान कर सकता है कि किस प्रकार अनेक विद्वानों ने इसके निर्माण में अपने विचारों और दृष्टिकोणों का योगदान दिया है। उन्होंने विशेष रूप से इस पुस्तक के तीन पात्रों जैसे गिरजा शंकर बाजपेयी, के.पी.एस. मेनन और सुबीमल दत्त पर ध्यान केंद्रित किया, और कैसे उन्होंने स्वतंत्रता पूर्व भारत में विभिन्न परिभाषित घटनाओं के संपर्क में आने से वातानुकूलित अलग-अलग वैश्विक विचार विकसित किए। इसके बाद चर्चा के तहत पुस्तक के लेखक डॉ. अमित दास गुप्ता, वरिष्ठ शोधकर्ता, यूनीवर्सिट डेर बुंदेवेर, मिंचेन, जर्मनी ने टिप्पणी की। उन्होंने पुस्तक लिखने की अवधि के दौरान किए गए प्रयासों और समर्थन को रेखांकित किया। पुस्तक के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पुस्तक ने राजनेताओं पर ध्यान केंद्रित नहीं बल्कि अक्सर अनदेखी किए गए तंत्र पर भारतीय विदेश नीति का इतिहास लिखने में नयापन अपनाया है। उन्होंने आगे कहा कि यह पुस्तक विदेश नीति के प्रति भारत के दृष्टिकोण और अन्य राजनीतिक शक्तियों के साथ उसके संबंधों को आकार देने वाले पहले प्रशासकों और राजनयिकों की गतिविधियों, रणनीतियों, वैश्विक विचारों और योगदानों का भी विश्लेषण करती है। विदेश मंत्रालय के पीपीएंडआर डिवीजन के संयुक्त सचिव डॉ. अनुपम रे ने पुस्तक की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने करियर डिप्लोमैट के नजरिए से इस पर विवेचन किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कहा कि यह पुस्तक भारतीय सिविल सेवाओं के इतिहास को रेखांकित करके एक महत्वपूर्ण अंतर को पूरा करती है। उन्होंने विशेष रूप से अपनी पुस्तक में व्यापक अभिलेखीय अनुसंधान और क्रॉस-रेफरेंसिंग के लिए लेखक की प्रशंसा की। प्रो. माधवन के पाल्ता ने अभिलेखीय शोध से भरी ऐसी विस्तृत पुस्तक लिखने के लिए लेखक को बधाई दी। उनकी टिप्पणी पुस्तक की प्रमुख थीसिस पर केंद्रित थी- जो भारतीय विदेश नीति 1947 से पहले उभरी थी। कॉलोनियों में तैनात भारतीयों ने भारत के लिए एक नीति तैयार की और इसी आधार पर बाद की विदेश नीति बनाई गई। उन्होंने लेखक के उस तर्क की भी आलोचना की जिसमें सुझाव दिया गया था कि नेहरू की कोई नीति नहीं है और उन्होंने भारत की विदेश नीति बनाने के अपने अनुभव के लिए आईसीएस की ओर रुख किया।

अगले वक्ता कार्नेगी इंडिया की निदेशक, डॉ. रुद्र चौधरी ने भी लेखक को भारतीय विदेश नीति के इतिहास पर कब्जा करने के लिए व्यापक, व्यावहारिक और असाधारण प्रयास पर बधाई दी। टाइमिंग के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सेवाओं के भारतीयकरण पर लिखने का यह एक बेहतरीन समय है। पुस्तक में उन छात्रों के लिए पढ़ने की सिफारिश की जाती है जो भारत की सुरक्षा में रुचि रखते हैं। अंतिम वक्ता डॉ. जोरावर दौलत सिंह ने लेखक को उनके उम्दा शोध और ब्रिटिश भारत और स्वतंत्र भारत में राजनीतिक शक्ति के शीर्ष को जीवंत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय तक इतिहासशास्त्र सलाहकारों के छोटे समूहों के बीच बातचीत के अधिक जटिल गतिशील के बजाय राजनीतिक प्राधिकरण के नेतृत्व पर रहता है। उन्होंने यह कहते हुए अपना वक्तव्य समाप्त किया कि आज की बहस 1940 और 1950 के दशक में हुई चर्चाओं से बहुत मिलती-जुलती हैं-चीन के सवाल पर भारत को कहां खड़ा होना चाहिए? भारत को महान शक्तियों के बीच कहां खड़ा होना चाहिए? कुछ क्षेत्रीय मुद्दों पर इसकी स्थिति क्या होनी चाहिए? उप-महाद्वीप में इसकी क्या भूमिका होनी चाहिए?

38 वां सप्रू हाउस व्याख्यान महामहिम श्री अब्दुल्ला शाहिद, मालदीव गणराज्य के विदेश मामलों के मंत्री और 76 वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा, 23 जुलाई 2021

मालदीव गणराज्य के विदेश मामलों के मंत्री और 76 वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्वाचित राष्ट्रपति महामहिम श्री अब्दुल्ला शाहिद ने ' प्रेसीडेंसी ऑफ होप-76 वें संयुक्त राष्ट्र महासभा: कोविड महामारी और सुधार बहुपक्षीयता की जरूरत ' पर 38 वें सप्रू हाउस व्याख्यान दिया। व्याख्यान की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत मंजीव सिंह पुरी ने की। भारतीय वैश्विक परिषद के पूर्व महानिदेशक डॉ. टी.सी.ए. राघवन ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि महामहिम श्री अब्दुल्ला शाहिद ने मालदीव में लोकतंत्र की चुनौतियों पर चौथा सप्रू हाउस व्याख्यान दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि द्वीपीय राष्ट्र जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय संस्थानों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सहयोग का सूरमा रहा है।

महामहिम शाहिद ने इस बात पर जोर देकर शुरुआत की कि मालदीव को भारतीय लोगों की उदारता पर पूरा भरोसा है। भारत ने 95 देशों में वैक्सीन भेजे हैं। दुनिया भर में महामारी के विभिन्न नतीजों को देखते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि कई देश कर्ज की गिरफ़्त में आ गए हैं और 20 साल में पहली बार वैश्विक गरीबी बढ़ने की संभावना है। दुनिया की 90 प्रतिशत से अधिक छात्र आबादी कोविड-19 से प्रभावित है। इसके अलावा, हम वर्तमान में बाढ़, लू, महामारी आदि से तबाह हो रहे हैं। लेकिन ऐसे अनगिनत लोग हैं जो भलाई के कार्यों में लगे हुए हैं। फिर भी, एक बेहतर कल का वादा हमें जीवित रख रहा है। महामहिम शाहिद ने कहा कि एक प्रेरक शक्ति के रूप में आशा के साथ लचीलापन बनाना संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने टीकाकरण तक सार्वभौमिक पहुंच के महत्व पर जोर दिया। जब तक हर कोई सुरक्षित नहीं है तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने दूसरी प्राथमिकता को रेखांकित किया कि स्थिरता का पुनर्निर्माण किया गया। कोविड-19 महामारी जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों की जगह नहीं है, जो केवल बिगड़ती जा रही है। उन्होंने दलील दी कि संयुक्त राष्ट्र को लोगों के करीब लाया जाना चाहिए और हमें निर्णय लेने में युवाओं की भागीदारी को पूरी तरह से सुनिश्चित करने की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि लैंगिक समानता उनके लिए एक और प्राथमिकता होगी और उनका कार्यालय लैंगिक-संतुलित होगा। सुधार बहुपक्षीयता के एजेंडे पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि 1970 के दशक में 10 देशों ने मालदीव सहित संयक्त राष्ट्र महासभा में सुधार की प्रक्रिया शुरू की। वर्तमान राजनीतिक वास्तविकताएं संयक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान ढांचे में परिलक्षित नहीं होती हैं। उन्होंने संयक्त राष्ट्र महासभा में सुधार की प्रक्रिया जारी रखने के लिए कुशल फैसिलिटेटर नियुक्त करने के अपने इरादे की घोषणा की उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि मालदीव संयक्त राष्ट्र महासभा की भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। अफगानिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का जिम्मा संयक्त राष्ट्र महासभा को सौंपा गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपने भविष्य को अपनाने में अफगान लोगों की सहायता करने के लिए एक साथ आना चाहिए।

डॉ. टीसीए राघवन विदाई, 23 जुलाई 2021

आईसीडब्ल्यूए-सीपीपीआर वर्चुअल सम्मेलन 'रणनीतिक वायदा: क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा परिसर', 18 अगस्त 2021

18 अगस्त, 2021 को 'स्ट्रैटेजिक फ्यूचर्स: रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स' पर एक दिवसीय आईसीडब्ल्यूए-सीपीपीआर सम्मेलन आयोजित किया गया था। वर्चुअल कांफ्रेंस का आयोजन आईसीडब्ल्यूए ने अपने एमओयू पार्टनर सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च (सीपीपीआर), कोच्चि के साथ संयुक्त रूप से किया था। आईसीडब्ल्यूए के राजदूत विजय ठाकुर सिंह ने उद्घाटन भाषण दिया। अपनी टिप्पणी में उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत स्वतंत्र, खुला, समावेशी, सुरक्षित और नियम आधार हिंद-प्रशांत के लिए प्रतिबद्ध है। राजदूत टीपी श्रीनिवासन ने अपने मुख्य भाषण में संयुक्त राष्ट्र में काम करने और समुद्री कानून के विकास और उसके आसपास के मुद्दों के अपने अनुभव को साझा किया। आईसीडब्ल्यूए से, तीन शोध अध्येता; डॉ. प्रज्ञा पांडे, डॉ. संकल्प गुर्जर और डॉ. विवेक मिश्रा ने क्रमश वेस्टर्न पैसिफिक रिम, वेस्टर्न हिंद महासागर और अरब सागर के तटवर्ती लोगों पर शोधपत्र प्रस्तुत किए। डॉ. प्रज्ञा पांडे ने अपनी प्रस्तुति में पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में गतिशील भू-राजनीतिक वातावरण पर ध्यान केंद्रित किया और किसी भी महत्वपूर्ण क्षेत्र व्यापक सुरक्षा वास्तुकला, भू-राजनीतिक प्रतियोगिताओं और अभूतपूर्व महामारी प्रेरित बदलावों के अभाव पर जोर दिया जिससे सत्ता का क्षेत्रीय संतुलन अनिश्चित नजर आता है। डॉ. संकल्प गुर्जर ने बताया कि पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में एस्केलेटर सुरक्षा की गतिशीलता नई नहीं है। यह क्षेत्र स्वेज नहर और शीत युद्ध के उद्घाटन के समय से ही संघर्ष के केंद्र में रहा है। इस तरह के जारी संघर्ष से आक्रोश की चुनौतियां विकसित हुई हैं डॉ. विवेक मिश्रा ने कहा कि अमेरिका के अफगानिस्तान से बाहर निकलने के मद्देनजर अन्य देशों के लिए अरब सागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिए बहुपक्षीय दृष्टिकोण अपनाने और साझेदारी करने के लिए एक नई जगह है।

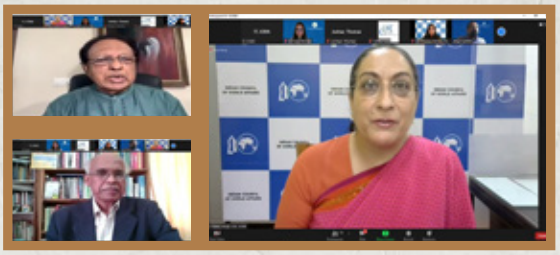

आईसीडब्ल्यूए-यूएसआई वेबिनार "संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों की प्रभावशीलता - संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों पर सैनिकों और विविधता की संरचना की गतिशीलता", 25 अगस्त 2021

भारतीय वैश्विक परिषद् (आईसीडब्ल्यूए) और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया (यूएसआई) ने 25 अगस्त 2021 को "संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों की प्रभावशीलता: सैनिकों की संरचना की गतिशीलता और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों पर विविधता" पर संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना पर तीसरे वेबिनार की मेजबानी की। वेबिनार ने विभिन्न सेना-योगदान करने वाले देशों (टीसीसी) से तैयार शांतिरक्षकों की संरचना और विविधता, उनकी विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथाओं और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों पर परिचालन व्यवहार पैटर्न के प्रभाव पर चर्चा की।

स्वागत भाषण जनरल पी.के. गोस्वामी, उप निदेशक (एएंडसी) (सेवानिवृत्त) यूएसआई ने दिया। इसके बाद आईसीडब्ल्यूए के महानिदेशक, राजदूत विजय ठाकुर सिंह ने भारत की सक्रिय भागीदारी और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सबसे बड़े सेना योगदानकर्ताओं में से एक होने पर कहा। उन्होंने इस बात की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया कि शांति और सुरक्षा को न केवल बनाए रखने के लिए शांति स्थापना की बहुआयामी भूमिका है बल्कि राजनीतिक अधिकारों को सुगम बनाने और कानून और व्यवस्था बहाल करने की भी। मुख्य भाषण, सुश्री पेरनीला रयदें, निदेशक, चैलेंजिज फोरम ने दिया कि संस्कृति, धर्म और भाषा को बढ़ावा देने और संघर्ष के समाधान और मिशन प्रभावशीलता सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के रूप में शांतिरक्षकों के मामले में विविधता पर जोर दिया गया था। वेबिनार को मेजर जनरल (डॉ.) बरदलानी ने मॉडरेट किया। वेबिनार के वक्ता स्वीडिश डिफेंस यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर और उपसाला विश्वविद्यालय के फेलो डॉ. चिआरा रूफा थे; कर्नल (डॉ.) के. के. शर्मा (सेवानिवृत्त), पूर्व सैन्य पर्यवेक्षक, यू एन टी ए सी; और कर्नल केकरे, कर्नल, सी यू एन पी के आई। समापन भाषण यूएसआई के निदेशक मेजर जनरल बी. के. शर्मा (सेवानिवृत्त) ने दिया, जिन्होंने शांति अभियानों का विश्लेषण करते हुए 21वीं सदी की चुनौतियों पर गौर करने की जरूरत पर कहा।

सप्रू हाउस पेपर (एसएचपी) चर्चा शीर्षस्थ 'दक्षिण पूर्व एशिया के लिए कनेक्टिविटी का निर्माण: भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग' डॉ. टेम्जेनमरेन एओ,अध्येता, आईसीडब्ल्यूए, 31 अगस्त, 2021

31 अगस्त, 2021 को दक्षिण पूर्व एशिया के लिए कनेक्टिविटी का निर्माण: भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग नामक एक सप्रू हाउस पेपर चर्चा आयोजित की गई थी। यह पेपर आईसीडब्ल्यूए के अध्येता डॉ. टेम्जेनमरेन एओ ने प्रस्तुत किया। इस पत्र पर आसियान इंडिया सेंटर, आरआईएस, नई दिल्ली के प्रो. प्रबीर दे की अध्यक्षता में विशेषज्ञों के एक प्रख्यात पैनल ने भारत-चीन और दक्षिण प्रशांत पर अध्ययन केंद्र के पूर्व प्रोफेसर डॉ. जी जयचंद्र रेड्डी, एस वी विश्वविद्यालय, तिरुपति और राजनीति विज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. बिप्लब देबनाथ, त्रिपुरा विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए पेपर पर टिप्पणी और बहुमूल्य सुझावों के साथ चर्चा की।

"भारत-प्रशांत आशियान पहल (आईपीओआई) पर राष्ट्रीय परामर्श", 3 सितंबर 2021

भारतीय वैश्विक परिषद् (आईसीडब्ल्यूए) ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से 3 सितंबर 2021 को हिंद-प्रशांत महासागर पहल पर राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया। इस परामर्श में लगभग विचार-विमर्श किया गया और भारत के 15 विशेषज्ञों ने भाग लिया। वक्ताओं ने समुद्री मामलों के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले शिक्षाविदों, वैज्ञानिक और नौसैनिक विश्लेषकों के एक बहु-अनुशासनात्मक समूह का गठन किया। परामर्श के दौरान हुई चर्चा में आईपीओआई अर्थात (क) समुद्री सुरक्षा के सात स्तंभ (ख) समुद्री पारिस्थितिकी; (ग) समुद्री संसाधन; (घ) क्षमता निर्माण और संसाधन साझा करना; (ङ) आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन; (च) विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अकादमिक सहयोग; और (जी) व्यापार, कनेक्टिविटी और समुद्री परिवहन शामिल थे।

उपरोक्त स्तंभ चार तकनीकी सत्रों में सामूहिक परामर्श दिया गया था। आईसीडब्ल्यूए के महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने भारत के इतिहास में महासागरों और समुद्रों के गहरे प्रभाव पर प्रकाश डाला और इसने अपने भविष्य को कैसे आकार दिया है। उन्होंने आगे कहा कि आईपीओआई साझेदारी बनाकर हितधारकों का एक समुदाय बनाना चाहता है। आईपीओआई के कई स्तंभों पर बढ़त लेते हुए भारत अन्य देशों को इस पहल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। उन्होंने भारत के इतिहास में महासागरों और समुद्रों के गहरे प्रभाव पर प्रकाश डाला और इसने अपने भविष्य को कैसे आकार दिया है। उन्होंने आगे कहा कि आईपीओआई साझेदारी बनाकर हितधारकों का एक समुदाय बनाना चाहता है। आईपीओआई के कई स्तंभों पर बढ़त लेते हुए भारत अन्य देशों को इस पहल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। विशेष उद्याकरण भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (आईएमयू) चेन्नई की कुलपति डॉ. मालिनी वी शंकर आईएएस (सेवानिवृत्त) ने दिया। उन्होंने हिंद-प्रशांत क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह लुक ईस्ट नीति और सागर से निकटता से जुड़ा हुआ है, आईपीओआई का उद्देश्य समान विचारधारा वाले देशों के साथ समुद्री सहयोग और साझेदारी को सुगम बनाना है। विदेश मंत्रालय की सचिव (पूर्व) श्रीमती रिवा गांगुली दास ने मुख्य भाषण दिया। उन्होंने हिंद-प्रशांत के परस्पर जुड़ाव के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया और क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार और समृद्धि के चालक के रूप में उभरे।

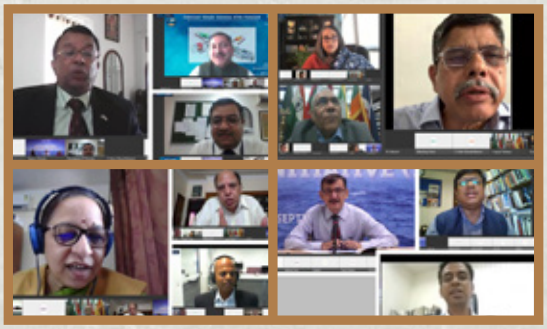

यू.एल. बरूआ द्वारा रचित पुस्तक "ए बांग्लादेश वॉर कमेंट्री" का विमोचन , बांग्लादेश सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री डॉ. हसन महमूद ने किया। 7 सितंबर 2021

उल बरूआ द्वारा आईसीडब्ल्यूए प्रकाशन "ए बांग्लादेश वॉर कमेंट्री" के शुभारंभ पर बांग्लादेश सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री डॉ. हसन महमूद, बांग्लादेश उच्चायोग नई दिल्ली के उच्चायुक्त डॉ. अंब मुहम्मद इमरान और हिंदू के वरिष्ठ एसोसिएट एडिटर अमित बरुआ ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। स्वागत भाषण देते हुए आईसीडब्ल्यूए के महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह ने उल्लेख किया कि भारत-बांग्लादेश राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 साल मना रहे हैं। साथ ही, इस वर्ष बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती और राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान की जन्म शताब्दी का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारत प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश की उल्लेखनीय प्रगति की प्रशंसा करता है। व्यावहारिक पुस्तक बांग्लादेश की मुक्ति के लिए लड़ने वाले लोगों को श्रद्धांजलि है।

बांग्लादेश उच्चायोग नई दिल्ली के उच्चायुक्त एएमबी मुहम्मद इमरान ने अपनी टिप्पणी देते हुए कहा कि बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता की भारी कीमत चुकाई है। अपनी आजादी के बाद से बांग्लादेश ने लंबा सफर तय किया है और सोनार बांग्ला का सपना साकार हुआ है, जो प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में साकार हुआ है। भारत ने अपने मुक्ति काल में बांग्लादेश के साथ रक्त साझा किया है। उन्होंने उल्लेख किया कि कैसे रेडियो ने इस अवधि के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अकादमिक मूल्य है। हिंदू के साथ-साथ लेखक के बेटे के वरिष्ठ एसोसिएट एडिटर अमित बरूआ ने कहा कि इन टिप्पणियों का लेखन श्री स्वर्गीय उल बरूआ की नौकरी का हिस्सा नहीं था। उन्होंने उन्हें अपने जुनून से बाहर लिखा। पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान के घटनाक्रम के बाद मुसलमानों के हितों की रक्षा का दावा नहीं करना चाहिए। वे मुस्लिम भाईचारे से सहमत नहीं हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि उम्मीद है कि बांग्लादेश का निर्माण अंतिम बार होना चाहिए कि धर्म को नरसंहार छेड़ने के लिए एक औजार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। बांग्लादेश जनसाइंसाकार सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सांसद डॉ. हसन महमूद ने अपना संबोधन देते हुए उल्लेख किया कि इस पुस्तक में आजादी से पहले और बाद में बांग्लादेश के लोगों की पीड़ा को दर्शाया गया है।

मुक्ति आंदोलन के दौरान पाकिस्तानी सेना मस्जिद को छोड़कर पूरे गांव को जला दिया करती थी। कई लोग जंगल की ओर भाग गए। उन्होंने कहा कि 9 महीने तक भारतीय मदद के बिना मुक्ति संभव नहीं होगी। भारत ने बांग्लादेश के नागरिकों को पड़ोसी राज्यों में शरण दी। श्रीमती इंदिरा गांधी विश्व जनमत बनाने के लिए दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में चली गईं, उनके प्रयास के बिना शेख मुजीबुर्रहमान को मुक्त करना मुश्किल होता। आज बांग्लादेश ने पाकिस्तान को सभी इंडेक्स में दरकिनार कर दिया है। पाकिस्तान की तुलना में यह पूरे क्षेत्र में लगभग एक दशक आगे है। क्षेत्रीय भलाई के एक हिस्से के रूप में, प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री शेख हसीना दोनों ही शारीरिक रूप से कनेक्टिविटी के साथ-साथ लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं।

डॉ. स्तुति बनर्जी द्वारा लिखित सप्रू हाउस पेपर (एसएचपी) चर्चा "चुप्पी तोडना: रूस और आर्कटिक में संयुक्त राज्य अमेरिका" पर चर्चा 8 सितंबर 2021

आईसीडब्ल्यूए की डॉ. स्तुति बनर्जी, अध्येता, ने 'चुप्पी तोडना: रूस और आर्कटिक में अमेरिका' शीर्षक से एक सप्रू हाउस पेपर चर्चा प्रस्तुत की। इस पेपर पर जेएनयू के रूस और मध्य एशिया अध्ययन केंद्र के पूर्व प्रोफेसर डॉ. अनुराधा चेनॉय की अध्यक्षता में विशेषज्ञों के आसन्न पैनल ने चर्चा की। प्रख्यात परिचर्चाकार, केरल के अंतरराष्ट्रीय संबंध केंद्रीय विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉ. उमा पुरुषोत्तमन और मुंबई के गेटवे हाउस के फेलो स्पेस एंड ओशियन स्टडीज प्रोग्राम डॉ. चैतन्य गिरि ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।

"ग्रैंड इथियोपिया के पुनर्जागरण बांध और जल बंटवारे की राजनीति- भारत से एक दृश्य" पर वेबिनार, 17 सितंबर 2021

आईसीडब्ल्यूए ने 17 सितंबर को "ग्रैंड इथियोपियाई पुनर्जागरण बांध और जल बंटवारे की राजनीति: भारत से एक दृश्य" पर एक वेब आधारित चर्चा का आयोजन किया। आईसीडब्ल्यूए के महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह ने उद्घाटन भाषण दिया। चर्चा की अध्यक्षता राजदूत (सेवानिवृत्त) गुरजीत सिंह ने की। पैनलिस्टों में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, बेंगलुरु में रिसर्च एसोसिएट अपूर्व सुधाकर, आईसीडब्ल्यूए में अध्येता डॉ. फ़ज़्ज़ुर रहमान सिद्दीकी, यूएन इंटरनेशनल लॉ कमीशन की सदस्य डॉ. अनिरुद्ध राजपूत और आईसीडब्ल्यूए शासी परिषद् के सदस्य और फेलो डॉ. उत्तम कुमार सिन्हा, मनोहर पर्रिकर इंस्टिट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, नई दिल्ली शामिल थे। इस जटिल मुद्दे के विभिन्न आयामों का विश्लेषण करने के लिए पैनल की संरचना की गई थी। इस चर्चा में जीईआरडी के संदर्भ में शामिल जटिलता और कई आयाम (जैसे ऐतिहासिक, राजनीतिक, इंजीनियरिंग, विकासात्मक आदि) सामने आए। जीईआरडी प्रकरण में भारत सहित दुनिया भर में अंतर-राज्यीय जल बंटवारे और जल सुरक्षा के लिए सबक और निहितार्थ हैं।

सर्बिया के विदेश मामलों के मंत्री महामहिम निकोला सेलाकोविच द्वारा विशेष व्याख्यान-भारत-सर्बिया संबंध: खेल और भविष्य की क्षमता की स्थिति, 20 सितंबर 2021

आईसीडब्ल्यूए ने 20 सितंबर 2021 को सर्बिया के विदेश मामलों के मंत्री एचई निकोला सेलाकोविच द्वारा भारत-सर्बिया संबंध: खेल और भविष्य की क्षमता की स्थिति पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया। स्वागत भाषण भारतीय वैश्विक परिषद् के महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह ने दिया, जिसके बाद महामहिम सिनिसा पावीक, इंचार्ज डी अफेयर्स, सर्बिया गणराज्य, नई दिल्ली के दूतावास द्वारा परिचयात्मक टिप्पणियों की गई। इसके बाद सर्बिया के विदेश मामलों के मंत्री महामहिम निकोला सेलाकोविच ने ' भारत-सर्बिया संबंध: स्टेट ऑफ प्ले एंड फ्यूचर पोटेंशियल ' पर अपना विशेष व्याख्यान दिया। भारतीय वैश्विक परिषद् के महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि सर्बिया और भारत के बीच घनिष्ठ संबंध हैं और दोनों देशों के बढ़ते प्रयासों के साथ इस संबंध को उच्चस्तरीय यात्राओं से चिह्नित किया गया है। हमारा इतिहास गुटनिरपेक्ष आंदोलन के गठन और दीक्षा का है। दोनों देश कई क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण और विस्तारित संबंध साझा करते हैं। यह प्राकृतिक साझेदारी भविष्य

के विकास और पारस्परिक क्षमता की खोज के लिए सहयोग करने के लिए विचारों और हितों की समानता से प्रेरित है। भारत सर्बिया को मध्य यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में देखता है।महामहिम श्री सिनिसा पावीक, राजदूत - सर्बिया गणराज्य के प्रभारी डी अफेयर्स ने अपनी टिप्पणी में कहा कि हमारे घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध परंपराओं, इतिहास और स्वतंत्रता के प्रति प्रेम के प्रति सम्मान को फलते-फूलते हैं। भारत-सर्बिया संबंधों का भविष्य संचार में समाहित होना चाहिए और आगे की साझेदारियों के लिए विचारों के आदान-प्रदान और चैनलों के उद्घाटन के लिए संभावनाएं पैदा करने का प्रयास किया जाना चाहिए। सर्बिया गणराज्य के विदेश मामलों के मंत्री महामहिम निकोला सेलाकोविच ने अपने विशेष व्याख्यान में ' सर्बिया ऑन द टॉपिक-भारत-सर्बिया संबंध: खेल और भविष्य की क्षमता की स्थिति ' शीर्षक से कहा कि भारत और सर्बिया राजनीति, व्यापार और संस्कृति में अपने इतिहास और पारस्परिक हितों के माध्यम से दृढ़ता से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सैन्य तटस्थता की अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सर्बिया व्यापक क्षेत्र का एकमात्र देश है और नाटो का सदस्य नहीं है। इसकी विदेश नीति ने विश्व स्तर पर देशों के साथ पारंपरिक रूप से सामंजस्यपूर्ण प्रयासों को संरक्षित करने के लिए आगे बढ़ाया है। महामहिम सेलाकोविच ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 2014 में नवनिर्वाचित सरकार को बाढ़ से निपटना था जिसके कारण उनकी कमजोर अर्थव्यवस्था और आगे घटी। हालांकि, वसूली बेरोजगारी की दर 26.9 प्रतिशत से 7 प्रतिशत से नीचे गिरने के साथ जल्दी किया गया है। पिछले साल के अंत तक सर्बिया ने इस क्षेत्र में 61 प्रतिशत एफडीआई को आकर्षित किया था। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सर्बिया के सकल घरेलू उत्पाद के + 6.5 प्रतिशत होने की भविष्यवाणी की है और देश खुद इसे एक 7 प्रतिशत होने की भविष्यवाणी करता है। कृषि पर काफी हद तक निर्भर होने से, जो अभी भी सकल घरेलू उत्पाद में ठोस 9.8 प्रतिशत का योगदान देता है, सर्बिया अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों के माध्यम से कई अन्य क्षेत्रों को समायोजित करने के लिए स्थानांतरित हो गया है और ऐसी कई और सहयोगी पहलों के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि सर्बिया का आधुनिक डिजिटल उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। सर्बिया ने प्रारंभिक स्कूल में एक अनिवार्य विषय के रूप में सूचना विज्ञान शुरू किया है। पिछले साल उनके पहले बैच में ग्रेजुएशन किया था। सर्बिया पर्यटन बढ़ाने, दोनों देशों की विविध पेशेवर पृष्ठभूमि से युवा पीढ़ियों के आदान-प्रदान के लिए भारत के साथ विभिन्न पहलुओं पर सहयोग या सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लिए काम करने के लिए तत्पर है, जिनमें से कुछ में फार्मास्यूटिकल्स, आईटी उद्योग आदि शामिल होंगे। इनके अलावा, लोगों से लोगों के बीच संबंध और नेतृत्व के उच्च स्तर के बीच बातचीत के लिए लगातार प्रवृत्ति स्थिर और समृद्ध द्विपक्षीय संबंधों के परिणामस्वरूप होगी। सर्बिया के दक्षिणी प्रांत द्वारा उठाए गए अलगाववादी मुद्दे के मामले में भारत ने सर्बियाई सरकार को अपना समर्थन दिखाया है।

"चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 वर्ष " पर वेबिनार, 28 सितंबर 2021

भारतीय वैश्विक परिषद् ने "चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सौ साल" पर एक वेबिनार का आयोजन किया। भारतीय वैश्विक परिषद् के महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह ने स्वागत भाषण दिया। वेबिनार को राजदूत नलिन सूरी ने मॉडरेट किया। इस अवसर पर प्रो. श्रीमती चक्रवर्ती, प्रो. कमल शील, प्रो. अविजित बनर्जी और प्रो. श्रीकांत कोंडापल्ली थे। यह चर्चा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) के विकास के विभिन्न चरणों पर केंद्रित थी।

चर्चा में यह बात प्रकाशित हुई कि पार्टी का जन्म 4 मई 1919, आंदोलन से हुआ था। चूंकि चीन पर शासन करने का कोई एक अधिकार नहीं था, इसलिए सरदारों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। सीपीसी को सीपीएसयू और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से समर्थन मिला। सीपीसी 1923 में कुममितांग (केएमटी) सरकार में शामिल हो गया। सीपीसी और केएमटी के बीच हितों का टकराव हुआ। माओ का मानना था कि किसानों और सरदारों के बीच विरोधाभास है। माओ ने किसानों के साथ काम करके अपना आधार समेकित किया और एक गुरिल्ला सेना का निर्माण किया जबकि चियांग काई शेक उत्तर में चुनाव प्रचार कर रहे थे। माओ का लंबा मार्च 1930 में हुआ था और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) का जन्म इस चरण के दौरान माओ के समय की भूलों जैसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड और सांस्कृतिक क्रांति हुई थी। हालांकि चीन ने औद्योगिक क्षमता और उत्पादन के मामले में लगातार विकास जारी रखा। माओ के बाद नेताओं ने पूंजीवादी घटनाक्रम की नीति को आगे बढ़ाया। वे देश को अमीर और मजबूत बनाना चाहते थे।

चर्चा में कहा गया, सौ साल में तीन सत्ता नेता माओ त्से तुंग, देंग जियाओपिंग और शी जिनपिंग रहे हैं। चार आधुनिकीकरण कार्यक्रम देंग जियाओपिंग के तहत शुरू हुए और चीन ने विदेशी निवेश आकर्षित करना शुरू कर दिया। उन्होंने शोध केंद्र खोलने का भी प्रस्ताव रखा। विदेश नीति के मोर्चे पर इस समय चीन ने अमेरिका और भारत के साथ अपने संबंधों को सामान्य कर दिया। देंग ने देश को स्थिर रखने की ठान ली थी और स्थिरता बनाए रखने के लिए बल प्रयोग करने के लिए तैयार थे। 1992 तक देंग जियाओपिंग के विचार ने माओ के बराबर का दर्जा प्राप्त कर लिया और वह सांस्कृतिक क्रांति की अस्थिरता से देश को बाहर निकालने में सफल रहे। उन्होंने ' वन-चाइल्ड पॉलिसी ' की शुरुआत की और अर्थव्यवस्था का विस्तार किया। समय की अवधि में, सीपीसी जीवन के सभी क्षेत्रों को कवर सभी शामिल हो गया है। चीन का परिवर्तन "एशिया के बीमार आदमी" से दुनिया में "दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था" के लिए जगह ले ली है। समग्र साक्षरता, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार दिखाई दे रहा है। आज चीन को ' मिडिल इनकम ट्रैप ', ' थुसिडीज ट्रैप ' और ' किंडलबर्जर ट्रैप ' जैसे कई जाल का सामना करना पड़ रहा है। विदेश नीति में मजबूती भी आई है और कोर इंटरेस्ट का दायरा बढ़ा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काफी एम्पावर्ड दिया जाता है। पार्टी पीएलए पर निर्भर है और "एक्टिव डिफेंस" की अवधारणा को काफी महत्व दिया जाता है। सीपीसी के तहत, 65 प्रतिशत शहरीकरण हुआ है जिसने चीन को एक किसान आधारित से शहरी मध्यवर्गीय लोकाचार में बदल दिया है। कुल मिलाकर चीन की सभी क्षेत्रों में पावरहाउस बनने की इच्छा है।

चर्चा के दौरान यह बताया गया कि शताब्दी दिवस समारोह में शी जिनपिंग ने कहा, हम कभी भी किसी को दमन करने की अनुमति नहीं देंगे, और

चीन को अधीन नहीं करेंगे। आज के चीन में राष्ट्रवाद, मार्क्सवाद और पूंजीवाद एक साथ मौजूद हैं। इन वैचारिक तख्तों में अंतर्निहित विरोधाभास हैं। सीपीसी चीनी विशेषताओं के साथ समाजवाद को लागू कर रहा है। सिद्धांत "सत्ता बंदूक के बैरल से बहती है और बंदूक पार्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है", शी जिनपिंग के तहत भी रखती है। शी जिनपिंग के इर्द-गिर्द एक तरह का व्यक्तित्व पंथ बनाया जा रहा है।

आउटरीच कार्यक्रम

"चीन और दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व-एशिया: भारत के लिए निहितार्थ" पर स्कूल ऑफ सोशल साइंस, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर द्वारा दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, 27-28 अगस्त 2021

गुरु नानक देव विश्वविद्यालय (जीएनडीयू), अमृतसर, पंजाब के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज ने 27-28 अगस्त 2021 को दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी "चीन और दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया: भारत के लिए निहितार्थ" का आयोजन किया। सेमिनार को आईसीडब्ल्यूए, नई दिल्ली ने आर्थिक रूप से समर्थन दिया। यह बात जीएनडीयू के स्कूल ऑफ सोशल साइंस द्वारा कोविड-19 महामारी के बाद से आयोजित पहली संगोष्ठी के बारे में कही गई। उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर सहित लगभग 30 प्रतिभागियों ने प्रस्तुतियां दी और कुछ प्रतिभागियों ने वर्चुअल मोड के माध्यम से भाग लिया। सेमिनार में विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने भी भाग लिया। सेमिनार में अध्येता डॉ.

अतहर जफर ने परिषद का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने संगोष्ठी के शैक्षणिक सत्र में एक पेपर भी प्रस्तुत किया। जीएनडीयू के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के अध्यक्ष प्रो. राजेश कुमार द्वारा संगोष्ठी विषय की शुरुआत के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रो. श्रीकांत कोंडापल्ली ने ऑनलाइन मुख्य भाषण दिया। उन्होंने दक्षिण एशिया और दक्षिणपूर्व एशिया के साथ चीन के ऐतिहासिक, आर्थिक और क्षेत्रीय कनेक्शन को रेखांकित किया। उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) और कॉमन डेस्टिनी के समुदाय सहित दोनों क्षेत्रों को शामिल करने के लिए चीन द्वारा की गई प्रमुख पहलों के बारे में बताया। विशेष संबोधन में राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एमेरिटस प्रो. करोरी सिंह ने क्षेत्र अध्ययन और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर शोध को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए आईसीडब्ल्यूए की सराहना की। उन्होंने कहा कि चीन ने अपनी आबादी का बड़ा हिस्सा गरीबी से बाहर निकाला है और मध्यम समृद्ध समाज के उद्देश्य को साकार किया है। दो दिवसीय संगोष्ठी में पांच

अकादमिक सत्र हुए जिसमें दक्षिण एशिया और दक्षिणपूर्व एशिया के साथ चीन के संबंधों के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया था, जिसमें सार्क और आसियान जैसे क्षेत्रीय समूह शामिल थे। अफगानिस्तान में विकसित हो रही स्थिति पर चर्चा की गई। समापन भाषण सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जेएनयू, नई दिल्ली के पूर्व चेयरपर्सन प्रो संजय भारद्वाज ने किया। उन्होंने क्षेत्र अध्ययन के महत्व को रेखांकित किया और छात्रों से अंतरराष्ट्रीय संबंधों में विषयगत अध्ययन पर भी ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।

पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के इंटरकनेक्शन पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी: “सामाजिक-आर्थिक संबंधों और भविष्य की संभावनाओं की ऐतिहासिक समझ" पश्चिम एशियाई अध्ययन केंद्र (CWAS), जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली, द्वारा आयोजित

18-19 सितंबर 2021

सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली ने 18-19 सितंबर 2021 को 'पश्चिम एशिआई देश के साथ भारत का इंटरकनेकशन: सामाजिक -आर्थिक सम्बन्ध और भावी परियोजनाओं की ऐतिहासिक समझ विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। यह संगोष्ठी भारतीय वैश्विक परिषद् द्वारा प्रायोजित की गई थी। इस दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में भारत-पश्चिम एशिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। यह मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित थी कि कैसे भारत और पश्चिम एशिया ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वे कभी भी एक-दूसरे के लिए विदेशी नहीं रहे हैं।

इस संगोष्ठी में जेएनयू के एसआईएस के डीन प्रोफेसर अविनी कुमार महापात्रा ने इस बारे में अपनी टिप्पणी की कि कैसे दुनिया एक के बाद के आधिपत्य की ओर बढ़ गई है, जहां अमेरिका ने वैश्विक क्षेत्र में अपनी पारंपरिक स्थिति खो दी है। उन्होंने अरब विद्रोह के बाद अरब राजनीति के बदलते प्रतिमान के बारे में भी विस्तार से निपटा और कैसे नए अभिनेता उभरे हैं जो क्षेत्रीय राजनीति के राजनीतिक प्रक्षेपवक्र को हुक्म दे रहे हैं इस दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में नब्बे के आसपास राष्ट्रीय संगोष्ठी विभिन्न विषयगत मुद्दों पर प्रस्तुत की गई। सेमिनार में अध्येता डॉ. फ़ज़्ज़ुर रहमान सिद्दीकी ने आईसीडब्ल्यूए का प्रतिनिधित्व किया और उद्घाटन सत्र में विशेष अतिथि रहे।

भारत त्रैमासिक
अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक जर्नल
खंड 77, अंक 3,
जुलाई-सितंबर, 2021

इंडिया क्वार्टरली के वर्तमान अंक में 8 लेख, एक समीक्षा निबंध और 3 पुस्तक समीक्षाएं हैं। प्रश्न जैसे लेख: लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर के साथ भारत के जुड़ाव से क्या उम्मीद की जाए? क्या बीजिंग का "मेड इन चाइना 2025" सफलता के लिए तैयार है?

सम्पादकीय

पिछले कुछ वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है, तनाव के तहत मौजूदा वैश्विक व्यवस्थाओं के साथ नई वास्तविकताओं और नई और पुरानी शक्तियों को अपने रिश्तों के आधार का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए कदम। इसलिए, पिछले कुछ वर्षों की बड़ी बहस उदार व्यवस्था के केंद्र में मानक सिद्धांतों और इन पर निर्मित संस्थानों के भविष्य के आकार का भाग्य रहा है। वैश्विक दक्षिण में, बहस दो विरोधाभासों पर टिकी है: उदारवादी अंतरराष्ट्रवाद की खींचतान और राष्ट्रवादी स्वायत्तता की विपरीत मांगों और निर्णय लेने वाले निकायों में विकासशील दुनिया को शामिल करने में विफलता के साथ वैश्विक के रूप में संस्थानों के प्रक्षेपण। हम भारत त्रैमासिक के इस मुद्दे को दो लेखों के साथ शुरू करते हैं, जो इन वाद-विवादों को सामने और केन्द्र में जगह देते हैं। हालांकि वे समावेशन और फिलीपन के आकर्षणों के लिए तर्क देते हैं, वैश्विक मानदंडों और व्यवस्थाओं के वजन को देखते हुए, वे घरेलू विचारधाराओं और परिस्थितियों से उभरने वाले दृष्टिकोणों को देखते हुए समावेशन पर भी सवाल उठाते हैं। सौभाग्य से, पिछले दशक में या तो, शामिल करने पर चुनौती और एजेंडा सेटिंग के दावों को एक ' ऊपर से नीचे ' दृष्टिकोण में स्थानांतरित कर दिया है। जलवायु परिवर्तन पर राजनीति, एक के लिए, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के पवित्र पोर्टलों से शहरों, टाउन हॉल और केरबसीडेस के लिए बहस हुई है। विकास एजेंडा अब केवल प्रमुख वैश्विक आर्थिक संस्थानों में सूचीबद्ध नहीं है बल्कि अफ्रीकी विकास बैंक जैसे क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों में भी ' बदलती वैश्विक शासन प्रणाली का एजेंट और अफ्रीका की विकास यात्रा में एक उभरते नेता ' हैं। न ही वे केवल राज्य की राजधानियों में नीति निर्माताओं द्वारा बहस और मांग कर रहे हैं, लेकिन यह भी दूरदराज के गांवों और क्षेत्रों में कस्बों में बातचीत का विषय है जहां सड़कों और कनेक्टिविटी स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए ऑक्सीजन हैं। इस मुद्दे में लेख इन चिंताओं के आसपास चर्चा की एक श्रृंखला प्रदान करते हैं, सकारात्मक परिवर्तन की भावना और सकारात्मक परिवर्तन के लिए एक मांग है कि राज्यों के बीच नीति बहस के लिए केंद्रीय होना चाहिए का संकेत है। लेकिन भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और क्षेत्रीय संघर्ष को लेकर पुरानी आशंकाएं कभी भी मौजूद हैं। इसलिए, जैसा कि हमारे लेखकों ने ध्यान दिया, चीन की ' मेड इन चाइना ' पहल ने विकसित अर्थव्यवस्थाओं और बीजिंग के बीच प्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकी युद्ध को प्रेरित किया है, यह देखते हुए कि नई प्रौद्योगिकियां चौथी औद्योगिक क्रांति की प्रेरक शक्ति होंगी। आर्थिक प्रभुत्व का दांव चीन ने जितना महसूस किया है, उतना ही ज्यादा है। दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के समुद्री दावे इंडोनेशिया जैसी इस क्षेत्र की मध्य शक्तियों को एक और लेख नोट के रूप में रोइंग कर रहे हैं। दक्षिण एशिया के हमारे अपने क्षेत्र में, बलूचिस्तान में संघर्ष एक स्थिरता है कि समाधान खारिज कर देता है और इस साल अफगानिस्तान से अमेरिका के हटने के बाद क्षेत्र में शांति पर अधिक असर पड़ेगा लगता है। जैसा कि हम कोविद-19 महामारी के दोहराने स्पाइक्स के लिए संभालो, यह क्षेत्र के लिए बुरी खबर के लिए कहते हैं।

मधु भल्ला
संपादक, इंडिया क्वार्टरली

आईसीडब्ल्यूए प्रकाशन

मुद्दा संक्षिप्त

1. डॉ. दीपिका सारस्वत, निवर्तमान हमास-इजरायल सैन्य टकराव: घरेलू, क्षेत्रीय संदर्भों और निहितार्थ को समझना (28 जून 2021)
2. डॉ. दीपिका सारस्वत, ईरान में रायसी की चुनावी जीत और उत्तराधिकार की लड़ाई (08 जुलाई 2021)
3. डॉ. नेहा मिश्रा, सीपीईसी कॉरिडोर में घटता चीनी निवेश: सदाबहार मित्रता पर पड़ता प्रभाव (12 जुलाई 2021)
4. डॉ. स्तुति बनर्जी, दो चुनावों की कहानी : मेक्सिको और पेरू 2021 (13 जुलाई 2021)
5. डॉ. अंकिता दत्ता, बिडेन की यूरोप यात्रा: ट्रांस-अटलांटिक के संदर्भ में एक नई शुरुआत है? (15 जुलाई 2021)
6. डॉ. स्तुति बनर्जी, राष्ट्रपति पुतिन के साथ राष्ट्रपति बिडेन की शिखर बैठक (22 जुलाई 2021)
7. डॉ. फ़ज़्ज़ुर रहमान सिद्दीकी, सीरिया में अराजकता के एक दशक में: असद राष्ट्रपति चुनाव में एक भारी जीत प्राप्त (16 अगस्त 2021)
8. डॉ. समथा मल्लेम्पति, एमडीपी और मालदीव में राजनीतिक घटनाक्रम के भीतर गुट: अस्थिर राजनीति की वापसी? (19 अगस्त 2021)
9. डॉ. अन्वेषा घोष, तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया: आगे क्या होगा? (25 अगस्त 2021)
10. डॉ. दीपिका सारस्वत, तालिबान के प्रति ईरानी दृष्टिकोण: परिवर्तन और निरंतरता को समझना (25 अगस्त 2021)
11. डॉ. फ़ज़्ज़ुर रहमान सिद्दीकी, मिस्र-इथियोपिया के ग्रैंड इथियोपिया पुनर्जागरण बांध पर गतिरोध जारी (25 अगस्त 2021)
12. डॉ. संजीव कुमार, अफगानिस्तान में हाल की घटनाओं की तुलना में चीन के घरेलू बहस और रणनीतिक उद्देश्य (27 अगस्त 2021)
13. डॉ. अंकिता दत्ता, यूरोपीय संघ के 'फिट फॉर 55 एजेंडा' का विश्लेषण (27 अगस्त 2021)
14. डॉ. स्तुति बनर्जी, बिडेन प्रशासन का एशिया पर ध्यानाकर्षण : चीन के प्रति प्रतिक्रिया का सृजन (06 सितंबर 2021)
15. डॉ. टेम्जेनमरेन एओ, मलेशिया में राजनीतिक परिवर्तन और इसका आर्थिक प्रभाव (07 सितंबर 2021)
16. डॉ. अंकिता दत्ता, यूरोप की अफगानिस्तान दुविधा (10 सितंबर 2021)
17. डॉ. स्तुति बनर्जी, 'सत्ता' में तालिबान: अफगानिस्तान में अमेरिकी भागीदारी के बीस साल (10 सितंबर 2021)
18. डॉ. जोजिन वी. जॉन, महामारी के दौर में राजनीति: पीएम सुगा के प्रस्थान के बाद, जापान में आगे क्या? (16 सितंबर 2021)
19. डॉ. अतहर जफर, अफगानिस्तान में तेजी से बदलाव और मध्य एशिया की प्रतिक्रिया (17 सितंबर 2021)
20. डॉ. तेशू सिंह, चीन–ताइवान के संबंधों में बढ़ते तनाव (23 सितंबर 2021)
21. डॉ. समथा मल्लेम्पति, भारत-श्रीलंका संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए श्रीलंका की एकीकृत राष्ट्र रणनीति (आईसीएस): मुख्य लक्ष्य एवं भविष्य की संभावनाएं (28 सितंबर 2021)
22. डॉ. स्तुति बनर्जी, कनाडा के चुनाव का एक सिंहावलोकन, (29 सितंबर 2021)
23. डॉ. ध्रुवज्योति भट्टाचार्य, बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना की हाल की संयुक्त राष्ट्र यात्रा, 30 सितम्बर 2021

दृष्टिकोन

1. डॉ राहुल नाथ चौधरी, भारत-यूरोपीय संघ एफटीए: वार्ता के प्रमुख कारक (7 जुलाई 2021)
2. डॉ. टेम्जेनमरेन एओ, म्यांमार के राजनीतिक संकट पर आसियान को है सामूहिक प्रतिक्रिया करने की जरुरत (09 July 2021)
3. डॉ. अन्वेषा घोष, हाशिए पर खड़ा अफगानिस्तान: अफगानिस्तान के क्षेत्रों पर तेजी से नियंत्रण करता तालिबान (12 जुलाई 2021)
4. डॉ. संकल्प गुर्जर, भारत की साइबर सुरक्षा: दृष्टिकोण और तत्परता पर एक नज़र (15 जुलाई 2021)
5. डॉ. तेशू सिंह, शी जिनपिंग की तिब्बत यात्रा (04 अगस्त 2021)
6. डॉ. संकल्प गुर्जर, क्या केवल अरब लोकतंत्र समाप्त हुआ है? अरब स्प्रिंग और ट्यूनीशिया में राजनीतिक संकट का एक दशक (10 अगस्त 2021)
7. डॉ. संकल्प गुर्जर, अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा: अफ्रीकी देशों की चिंता (03 सितंबर 2021)
8. डॉ. समथा मल्लेम्पति, श्रीलंका द्वारा खाद्य संकट को टालने के लिए आपातकालीन नियम लागू किया जाना: कारण, प्रतिक्रियाएं और निहितार्थ (15 सितंबर 2021)
9. डॉ. प्रज्ञा पांडे, रक्षा और सुरक्षा संबंधों को मजबूत बनाने के लिए भारत और आस्ट्रेलिया के बीच आरंभिक '2+2' वार्ता (15 सितंबर 2021)
10. डॉ. अन्वेषा घोष, अफगानिस्तान में महत्वपूर्ण खिलाड़ के रूप में क़तर का उदय (15 सितंबर 2021)
11. डॉ. विवेक मिश्रा, अफगानिस्तान में अस्थिरता दर्शाती कूटनीतिक शून्य भरने की दौड़ (15 सितंबर 2021)
12. डॉ. राहुल नाथ चौधरी, बांग्लादेश में तेज गति से होता आर्थिक विकास और इसकी भविष्य की चुनौतियां (23 सितंबर 2021)
13. डॉ. ध्रुवज्योति भट्टाचार्य, बांग्लादेश और नेपाल के मध्य ऊर्जा सहकारिता को लेकर बढ़ती सहक्रियता (23 सितंबर 2021)
14. डॉ. राहुल नाथ चौधरी, श्रीलंका में विदेशी मुद्रा संकट का कारण क्या है? (24 सितंबर 2021)
15. डॉ. अंकिता दत्ता, लिथुआनिया– चीन गतिरोध का आकलन (27 सितंबर 2021)
16. डॉ. प्रज्ञा पांडे, औपचारिक रणनीति की घोषणा के साथ यूरोपीय संघ ने हिंद– प्रशांत को अपनाया (27 सितंबर 2021)
17. डॉ. फ़ज़्ज़ुर रहमान सिद्दीकी, दशक में पहली बार इजरायली प्रधानमंत्री की इजिप्ट यात्रा: समीक्षा (27 सितंबर 2021)
18. डॉ. दीपिका सारस्वत, इब्राहिम रईसी की सरकार और इसकी एससीओ सदस्यता के तहत ईरान की विदेश नीति का नज़रिया (28 सितंबर 2021)
19. डॉ. अंकिता दत्ता, ट्रान्साटलांटिक गठबंधन और एयूकेयूएस (30 सितंबर 2021)

विशेष रिपोर्ट

20. डॉ. राहुल नाथ चौधरी, महामारी की शुरुआत के बाद से मजबूत हुई है क्वाड साझेदारी (17 जुलाई 2021)
21. डॉ. अन्वेषा घोष, क्या तालिबान 2.0 है? वर्तमान को समझने के लिए अतीत को प्रतिबिंबित करना (06 August 2021)

संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत

22. राजदूत अशोक मुखर्जी, 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत: जुलाई 2021 के लिए मासिक संक्षिप्त एशिया, अफ्रीका और सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित'।

23. राजदूत अशोक मुखर्जी, 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत: अगस्त 2021 के लिए मासिक संक्षिप्त यूएनएससी, अफगानिस्तान में भारत के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर फोकस'।

24. राजदूत अशोक मुखर्जी, 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत: सितम्बर 2021 के लिए मासिक संक्षिप्त एशिया, अफ्रीका और विषयगत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित'।

पुस्तक

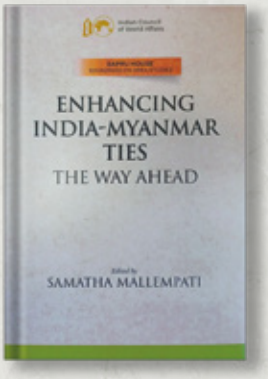

Enhancing India-Myanmmar Ties The Way Ahead,

Edited by Samatha Mallempati,

(Indian Council of World Affairs; KW Publishers, 2021)

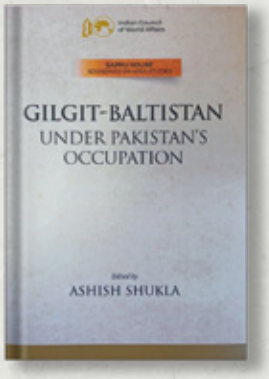

Gilgit-Baltistan Under Pakistan's Occupation,

Edited by Ashish Shukla,

(Indian Council of World Affairs; KW Publishers, 2021)

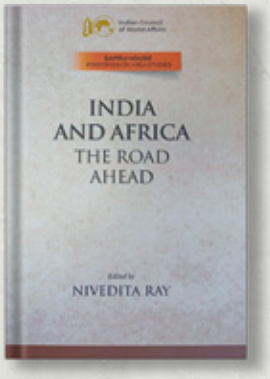

India and Africa The Road Ahead,

Edited by Nivedita Ray,

(Indian Council of World Affairs; KW Publishers, 2021)

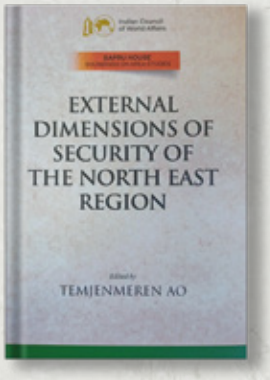

External Dimensions of Security of the North East Region,

Edited by Temjenmeren Ao,

(Indian Council of World Affairs; KW Publishers, 2021)

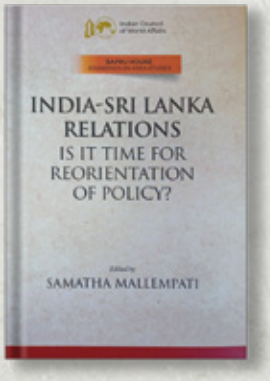

India-Sri Lanka Relations Is It Time for Reorientation of Policy,

Edited by Samatha Mallempati,

(Indian Council of World Affairs; KW Publishers, 2021)

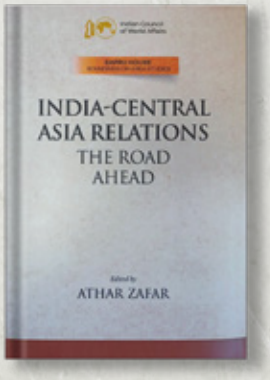

India-Central Asia Relations The Road Ahead,

Edited by Athar Zafar,

(Indian Council of World Affairs; KW Publishers, 2021)

आईसीडब्ल्यूए के बारे में

भारतीय वैश्विक परिषद् (आईसीडब्ल्यूए) की स्थापना 1943 में सर तेज बहादुर सप्रू और डॉ. एचएन कुंजरू के नेतृत्व में प्रख्यात बुद्धिजीवियों के एक समूह द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भारतीय परिप्रेक्ष्य तैयार करना और विदेश नीति के मुद्दों पर ज्ञान और सोच के भंडार के रूप में कार्य करना था। परिषद आज इन-हाउस फैकल्टी के साथ-साथ बाहरी विशेषज्ञों के माध्यम से नीतिगत अनुसंधान आयोजित करती है। यह नियमित रूप से सम्मेलनों, सेमिनारों, गोलमेज चर्चाओं, व्याख्यानों सहित बौद्धिक गतिविधियों की एक सरणी का आयोजन करता है और प्रकाशनों की एक श्रृंखला लाता है। इसमें एक सुसज्जित पुस्तकालय है, एक सक्रिय वेबसाइट है, और 'इंडिया क्वार्टरली' जर्नल प्रकाशित करती है। आईसीडब्ल्यूए ने अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बेहतर समझ को बढ़ावा देने और आपसी सहयोग के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक और अनुसंधान संस्थानों के साथ 50 से अधिक समझौते ज्ञापन किए हैं। परिषद की भारत में अग्रणी अनुसंधान संस्थानों, थिंक टैंक और विश्वविद्यालयों के साथ भी साझेदारी है।

मेंटर : राजदूत विजय ठाकुर सिंह, महानिदेशक, आईसीडब्ल्यूए, सप्रू हाउस, नई दिल्ली

संपादक : सुश्री नूतन कपूर महावर, संयुक्त सचिव, आईसीडब्ल्यूए, सप्रू हाउस, नई दिल्ली

प्रबंध संपादक : डॉ. निवेदिता रे, निदेशक अनुसंधान, आईसीडब्ल्यूए।

सहायक संपादक : डॉ. ध्रुवज्योति भट्टाचार्य, अध्येता, आईसीडब्ल्यूए।

हमसे जुड़ें

/Sapru.House | @ICWA_NewDelhi | /ICWA_NewDelhi | www.icwa.in

आईसीडब्ल्यूए, सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली - 110001 द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रक
वेबसाइट: http://www.icwa.in; दूरभाष नं 011-23317246 फैक्स नंबर 011-23310638